Title: Need to appoint C.B.I. as the sole agency for proper investigation of the case cooperative Bank Stock Scandal in Maharashtra.

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार मानता हूं कि चेयर की तरफ से मुझे किरीत सौमेया न कहकर किरीट सौमेया बोला जा रहा है। आप भी मुम्बई-महाराट्र के रहने वाले हैं। इसलिए आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुम्बई और महाराट्र में को-आपरेटिव बैंक में जो घोटाला हुआ, उसमें 600 करोड़ रुपये से ज्यादा डूब गये हैं। होम ट्रेड के संजय अग्रवाल को महाराट्र सरकार ने 14 दिन तक अरैस्ट नहीं किया। इतना ही नहीं रिजर्व बैंक और स्टेट को-आपरेटिव मिनिस्ट्री के डायरेक्टर्स ने अलग-अलग बैंक को जिला सहकारी बैंक और उस्मानाबाद सहकारी बैंक को नोटिसेस दिये थे कि इन बोड्र्स को डिज़ाल्व करो तो बोर्ड और वहां के आफिसर्स ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा कि यह नियम क्या है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी 14 अलग-अलग एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सेबी, प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर, लेबर मिनिस्ट्री, इकानोमिक आफेन्सिस ऑफ गुजरात गवर्नमैंट, इकानोमिक आफेन्सिस ऑफ महाराट्र गवर्नमैंट, गुजरात गवर्नमैंट, मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि। ये 14 अलग-अलग एजेंसीज इसकी इंक्वायरी कर रही हैं। इसमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टीगेशन नहीं हो रहा है। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच सी.बी.आई. को देनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टेक्नीकल एक्सपर्ट नॉलेज है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्वेस्टीगेशन में को-आर्डिनेट करना चाहिए। इसमें एक लाख तक के डिपॉजिटर्स हैं और उनका डिपॉजिट इंश्योरेंस कार्पोरेशन के अन्तर्गत सिक्योर्ड है, इस प्रकार की घोाणा केन्द्र सरकार, आर.बी.आई. और वित्त मंत्रालय को करनी चाहिए। मैं आपके द्वारा यह भी कहना चाहूंगा कि अभी तक 19 बैंकों के नाम आये हैं लेकिन महाराट्र में ऐसी सैंकड़ों को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज हैं जिन्होंने गवर्नमैंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमैंट किया है। उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। आज पता चला है कि पब्लिक सैक्टर के एक बैंक ने भी अपना पैसा होम ट्रेड के थ्रू डिपाजिट किया है। प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर ने बताया कि प्रॉविडेंट फंड के 92 करोड़ रुपये होम ट्रेड के घोटाले में फंस चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार से यह कहा जाये कि वह महाराट्र सरकार के साथ बातचीत करके उसको निर्देश दे कि सभी कागज-पत्र जांच के लिए सी.बी.आई. को सुपुर्द किये जायें। मेरा कहना है कि 24 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स हैं और वे आज चिन्ता कर रहे हैं कि उनके डिपॉजिट का क्या होगा ? मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके डिपॉजिट को सुरक्षित करने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाये।